(c) The C&F Value of the Potash imported during 1987-88 and 1988-89 was Rs. 160.88 crores and Rs. 298.681 crores respectively.

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मजदूरी की अदायगी

1281. **श्री शान्ति त्यागी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर रोजगार योजना के अधीन यह निदेश दिया गया है कि किसी भी कार्य पर व्यय की गई राशि का कम से कम 50 प्रतिशत मजूरी के नगद भुगतान पर किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ईंटों के ऊंचे मूल्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाईयां उत्पन्न करेंगे और ग्राम प्रधानों द्वारा बनायी गयी गांव विकास योजनाओं में रुकावट डालेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पंचायतों को निर्माण कार्य के लिए भट्टा मालिकों से सस्ती दरों पर ईंटें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गैर-मजदूरी घटक पर 50 प्रतिशत से अधिक खर्च को योजना निधियों के बाहर से पूरा किया जाना है । ईंटों की ऊंची कीमतों के बारे में मामला न तो भारत सरकार के ध्यान में लाया गया है और न ही इसका प्रस्ताव सस्ती दर पर ईंटें सप्लाई करने का है । यह स्थानीय कार्यान्वयन अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वे यथा संभव अच्छे से अच्छे तरीके से समस्या का समाधान करें जिसमें ईंटों का सीधा निर्माण शामिल है यदि इसकी आवश्यकता महसूस की जाए ।

Decontrolling the import of newsprint

1282. **SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE**: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Indian Newspaper Society had demanded, through a deputation which called on the Prime Minister in the first/second week of June, 1989, to decontrol the import of newsprint and to allow its import under open General Licence, with a view to help the industry to overcome the shortage of this commodity; and

(b) if so, what are the details of the demand made and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (PROF. K. K. TEWARY): (a) and (b) Some members of the Indian Newspapers Society informally met the Prime Minister on 7th June, 1989 and mentioned about the newsprint problem. On the basis of the directives given by the Prime Minister, a Group of Secretaries comprising of Secretaries of Finance, Industrial Development, Commerce and Information & Broadcasting was asked to look into the problems relating to newsprint. Based on the outcome of the discussions of the Group, steps have been taken to provide additional foreign exchange required for the import of newsprint and to extend customs duty relief on glazed newsprint to the small and medium newspapers who are entitled to allocations of glared newsprint as per the Newsprint Allocation Policy for 1989-90.

Villages without potable water in Uttar Pradesh

1283. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the number of villages in Uttar Pradesh which are still without potable water facility; and

(b) what is the number of villages in that state which have been pro-